

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में बन रही हैं या बनेंगी ;

(ग) उन सहकारी समितियों के सदस्य कौन-कौन लोग रहेंगे ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को क्या सहायता प्रदान करेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में वन श्रम सहकारी समितियां गठित की गई हैं । दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की समितियों को गठित करने के लिए प्रोत्साहन देने का विचार है ।

(ग) वन श्रम सहकारी समितियों के सदस्य मुख्यतः वन में काम करने वाले लोग जो कार्य-क्षेत्र में ही रहते हैं और थोड़े से सहानु-भूति रखने वाले या सामाजिक कार्यकर्ता हैं ।

(घ) राज्य सरकारों के वित्तीय सहायता के प्रतिरूप अपने-अपने हैं । केन्द्रीय सरकार पिछड़ी जातियों की कल्याण निधि में से सहायता देती है । पिछड़ी जातियों की सहकारी विशेष कार्यकारी दल ने कुछेक सिफारिशें कीं, जिन पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ।

घोड़े पालने वाले फार्म

५७२. श्री भक्त दर्शन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ अप्रैल, १९६३ के अतारंकित प्रश्न संख्या २२१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में एक अश्व प्रजनन फार्म की स्थापना में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उत्तर प्रदेश में इस फार्म की स्थापना के लिए स्थान पर विचार किया जा रहा है । फिर भी इस सम्बन्ध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है ।

Conversion of Narrow Gauge line between Latur and Miraj

573. Shri Sonavane: Will the Minister of Railways be pleased to state the progress made in the matter of conversion of narrow gauge line between Latur and Miraj on the Central Railway?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): The Project is not included in the Railways' programme of construction/conversion of lines during the Third Plan Period. Earlier investigations for conversion of this section have revealed that the project would be unremunerative and hence the proposal was dropped.

Employees of Lighthouses

574. Shri Jashvant Mehta: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that arrears due to employees of lighthouses in Gujarat area have not been paid as per recommendation of Second Pay Commission; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Claims of all employees of Lighthouses in Gujarat area have been settled except those of sixteen persons. Bills in respect of eight of them are under preaudit and those of the remaining eight have been returned by the Accountant General and are under further examination.